

राज्ये सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याद2049
16 दिसम्बर2015 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2049. श्री मेघराज जैन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि इस्पात क्षेत्र में नए निवेश में कमी आई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार द्वारा घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और इस्पात क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और
- (ग) यदि हां, तो किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात और खान राज्यो मंत्री

(श्री विष्णुपदेव साय)

(क): इस्पात क्षेत्र विशेषतः निजी क्षेत्र में निवेश इसकी सम्भावना उत्साहीहवर्द्धक न होने के कारण सुलभ नहीं रहे हैं , क्योंकि वर्तमान में विश्व में अतिरिक्तक क्षमता विद्यमान है और विशेषतः चीन में 250-300 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता उपलब्धी है , जिसकी वजह से इस्पात की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट हुई है और आयातों में वृद्धि हुई है तथा परिणामतः विद्यमान घरेलू इस्पात कंपनियों पर वित्तीय दबाव पड़ा है।

(ख) से (ग): भारत सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करने और इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- (i) लौह अयस्कल से समृद्ध झारखण्डक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में बड़ी क्षमता की ग्रीन फील्डन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्पेतशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्रेमवर्क अपनाया गया है।
- (ii) सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों ने इस्पात उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए विस्तार योजनाएं हाथ में ली हैं। सेल ने अपनी क्रूड इस्पात उत्पादन क्षमता को 12.8 एमटीपीए से बढ़ाकर 21.4 एमटीपीए करने के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार योजना हाथ में ली है। आरआईएनएल ने अपनी क्षमता को 3 एमटीपीए से 6.3 एमटीपीए करने के लिए विस्तार कार्य हाथ में लिये हैं। एनएमडीसी ने 3 एमटीपीए क्षमता के एक नए इस्पात संयंत्र की स्थापना का कार्य आरम्भक किया है।
- (iii) कोयला ब्लाटक के आवंटन को सरल बनाने के लिए दिनांक 30.03.2015 को 'कोल माईन्सज (स्पेतशल प्रोविजंस) अमेंडमेंट एक्ट 2015' अधिसूचित किया गया है।
- (iv) खनन पट्टे प्रदान किये जाने को सरल बनाने के लिए दिनांक 27.03.2015 को 'माईन्सई एण्डअ मिनरल्स (डेवलेपमेंट एण्डन रेग्यूलेशन्स) एमेंडमेंट एक्ट 2015' अधिसूचित किया गया है।
- (v) सरकार ने इस्पात के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और आयात के लिए दिनांक 12.03.2012 को 'स्टील एण्ड स्टील प्रोडक्ट (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर (अंतिम बार दिनांक 04.12.2014 को यथासंशोधित) अधिसूचित किया है।